ब्रिक्स @20 अब समझदार हो गया है

किसी के खिलाफ नहीं, पर किसी का मोहताज भी नहीं : मोदी

नई दिल्ली, 12 सितंबर. ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने कहा कि हमें अगले 20 सालों के लिए एक नए और बड़े एजेंडे पर काम करने की जरूरत है. हमें यह प्रोसेस अपने अंदरूनी वर्किंग सिस्टम से शुरू करना होगा. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स समिट की शनिवार को शुरुआत हो गई.

पीएम नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन समेत तमाम देशों के नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया. इसके बाद, पीएम मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स चेयरमैनशिप को सफल बनाने में आपके एक्टिव योगदान और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. इस साल का ब्रिक्स समिट एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है. हम इसकी 20वीं सालगिरह मना रहे हैं. इंसान की जिंदगी में 20 साल की उम्र मैच्योरिटी और जिम्मेदारी के एक नए दौर की शुरुआत होती है. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स किसी के खिलाफ नहीं है. साथ आगे बढ़ने के लिए किसी का मोहताज भी नहीं है.

20 साल के एजेंडे पर जोर

पीएम मोदी ने कहा, हमें अगले 20 सालों के लिए एक नए और बड़े एजेंडे पर काम करने की जरूरत है. हमें यह प्रोसेस अपने अंदरूनी वर्किंग सिस्टम से शुरू करना होगा. हालांकि ब्रिक्स प्रेसीडेंसी हर साल बदलती रहती है, लेकिन इससे हमारे इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए. मैं ब्रिक्स कंटिन्यूटी और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म बनाने का प्रस्ताव करता हूं. इससे 'ट्रोइका' अरेंजमेंट के जरिए सभी इनिशिएटिव और नतीजों का फॉलो-अप किया जा सकेगा. हम हर फैसले से जुड़े नोडल पॉइंट, टाइमफ्रेम और इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस को रिकॉर्ड करने के लिए एक सुरक्षित डिजिटल रिपॉजिटरी भी बना सकते हैं.

यूएनएससी पर चीन को संदेश

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स समिट में सदस्य देशों के बीच नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव दिया. साथ ही, उन्होंने चीन को संदेश देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिफॉर्म को अब और नहीं टाला जा सकता. जिस समय पीएम मोदी यह बोल रहे थे, उस समय चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहीं पास में ही बैठे थे. चीन ही यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता पर अड़ंगे लगाता रहा है.

नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया

ब्रिक्स में पीएम मोदी ने उठाया नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट में नाविकों की सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया और कहा कि नाविक ग्लोबल ट्रेड में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, फिर भी मुश्किल समय में उन्हें अक्सर सपोर्ट की कमी महसूस होती है. मेरा सुझाव है कि हम एक नाविकों का इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बनाएं. यह संबंधित देशों के समुद्री अधिकारियों और डिप्लोमैटिक मिशनों को जोड़ेगा, जिससे संकट की चेतावनी, मेडिकल मदद, परिवार को जानकारी देने और लोगों को निकालने में मदद मिलेगी।

ब्रिक्स पर एक नजर

'ब्रिक' नाम किसने दिया

'ब्रिक' शब्द किसी सरकार ने नहीं बनाया था. इसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने 2001 में अपनी एक शोध रिपोर्ट में इस्तेमाल किया था. उस समय वह गोल्डमैन सैक्स के मुख्य अर्थशास्त्री थे. उन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन को तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में बताते हुए 'ब्रिक' शब्द का इस्तेमाल किया. बाद में इन चार देशों ने राजनीतिक शिखर सम्मेलन शुरू किए. पहला ब्रिक शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ. दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ और 'ब्रिक' से 'ब्रिक्स' बन गया.

ब्रिक्स सैन्य गठबंधन नहीं

ब्रिक्स नाटो जैसा सैन्य गठबंधन या साझा विदेश नीति वाला औपचारिक राजनीतिक गुट नहीं है. यह सदस्य देशों के बीच व्यापार, वित्त, विकास, तकनीक, स्वास्थ्य और वैश्विक शासन जैसे क्षेत्रों में सहयोग का मंच है. इसके सदस्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अलग-अलग रुख भी रख सकते हैं.

ब्रिक्स का अपना विकास बैंक है

न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स के पांच मूल सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने की थी. इसका मुख्यालय शंघाई में है. इसके क्षेत्रीय कार्यालय जोहान्सबर्ग, साओ पाउलो, अहमदाबाद और मॉस्को में हैं. बैंक बुनियादी ढांचे और सतत विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराता है.

दुनिया की आधी आबादी ब्रिक्स सदस्य देशों में

2026 में ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों की कुल आबादी करीब 4.01 अरब बताई गई है. दुनिया की अनुमानित आबादी 8.30 अरब है. यानी ब्रिक्स देशों में दुनिया की करीब 48.3 प्रतिशत आबादी रहती है. आसान भाषा में कहें तो दुनिया के हर दो लोगों में लगभग एक व्यक्ति ब्रिक्स के किसी सदस्य देश में रहता है.

ब्रिक्स का अपना 'शेरपा'

ब्रिक्स शेरपा किसी सदस्य देश का वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होता है, जो शिखर सम्मेलन से पहले होने वाली बातचीत और तैयारियों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है. शेरपा घोषणापत्र तैयार करने, अलग-अलग मुद्दों पर बातचीत करने और सदस्य देशों के बीच सहमति बनाने में भूमिका निभाते हैं. 'शेरपा' शब्द हिमालय के शेरपा समुदाय से आया है, जो पर्वतारोहियों को पहाड़ों पर रास्ता दिखाने के लिए जाने जाते हैं.

भारत मंडपम में डिनर डिप्लोमेसी

गाला डिनर में परोसा गया भारत का विविध जायका

नई दिल्ली,12 सितंबर.18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन की गंभीर भू-राजनीतिक वार्ताओं और बंद कमरों की कूटनीति के बाद, शनिवार शाम को भारत मंडपम का माहौल बेहद भव्य और सांस्कृतिक सौहार्द से सराबोर हो गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों, वैश्विक नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के सम्मान में भारत मंडपम के लेवल-3 पर एक भव्य गाला डिनर का आयोजन किया, जिसे वैश्विक कूटनीति के गलियारों में स्वादिष्ट डिनर डिप्लोमेसी के रूप में देखा जा रहा है.

दिनभर के कूटनीतिक तनाव को कम करने और अनौपचारिक बातचीत का सहज माहौल तैयार करने के लिए आयोजित इस शाम की शुरुआत बेहद सुरीले अंदाज में हुई, जहां सौ से अधिक भारतीय और ब्रिक्स सदस्य देशों के कलाकारों के एक विशाल समूह ने अपनी लाइव संगीतमय प्रस्तुतियां दीं. इन कलाकारों ने पारंपरिक वाद्ययंत्रों और लोक धुनों के जरिए भारत के सांस्कृतिक वैभव और वैश्विक एकजुटता की खूबसूरत मिसाल पेश की, जिसने आयोजन स्थल पर मौजूद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन सहित सभी मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया. रात्रिभोज में मेहमानों को उत्तर प्रदेश के मशहूर अवधी गलौटी कबाब और लजीज हैदराबादी बिरयानी परोसी गई, जिसने भारतीय व्यंजनों की समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया. इसके साथ ही पारंपरिक स्वादों को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र की कुरकुरी भाकरवड़ी, दिल्ली और राजस्थान की प्रसिद्ध चटपटी कचौड़ियों ने मेहमानों का जायका बदला. मिलेट्स को बढ़ावा देने की भारत की वैश्विक मुहिम के तहत सेहत और पर्यावरण के अनुकूल रागी डोसा को भी इस शाही थाली में विशेष स्थान दिया गया, जबकि कश्मीर के खास मसालेदार अखरोट, पश्चिम बंगाल की कुचो निमकी और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से प्रेरित खास कमल के अर्क से बनी मिठाइयों ने इस राजकीय भोज में मिठास घोलने का काम किया.

आतंक को बर्दाश्त नहीं करने का ब्रिक्स ऐलान

शिखर सम्मेलन में गूंजा पहलगाम आतंकी हमला, समूह देशों ने की कड़ी निंदा

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 12 सितंबर. भारत मंडपम में 18वां ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन की सामूहिक चर्चा के बाद जारी किए घोषणापत्र में सदस्यों ने हर तरह से आतंकवाद की कड़ी निंदा की.

उनका कहना है कि चाहे मकसद, जगह या उसे अंजाम देने वाला कोई भी हो, आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ब्रिक्स देशों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की भी आलोचना की, जिसमें 26 लोग मारे गए थे और कई घायल भी हो गए.

मतभेदों के बीच एकसुर

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने भी बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का पुरजोर समर्थन किया और पश्चिमी देशों के एकतरफा प्रतिबंधों को वैश्विक व्यापार में सबसे बड़ी बाधा करार दिया. जानकार मान रहे हैं कि ब्रिक्स ने यह साबित कर दिया है कि आंतरिक मतभेदों के बावजूद यह समूह एक साझा आर्थिक और राजनीतिक एजेंडे पर एकजुट हो सकता है. भारत ने इस सम्मेलन के माध्यम से खुद को एक संतुलित और जिम्मेदार सुधारक शक्ति के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित किया है, जिसने समूह को किसी पश्चिमी विरोधी गुट में बदलने के बजाय एक न्यायसंगत आर्थिक मंच बनाने पर ध्यान केंद्रित रखा. नई दिल्ली शिखर सम्मेलन से दुनिया को यह साफ संदेश गया है कि भविष्य की वैश्विक व्यवस्था अब कुछ चुनिंदा विकसित देशों के इशारों पर नहीं चलेगी, बल्कि ग्लोबल साउथ की उभरती अर्थव्यवस्थाएं अब वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक नियमों को तय करने में बराबर की हिस्सेदार और मार्गदर्शक बन चुकी हैं.

घोषणापत्र में आतंक खिलाफ कई बिंदु

ब्रिक्स के घोषणापत्र में सीमा-पार आतंकवाद, आतंकवाद के लिए फंडिंग और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मिलने जैसी समस्याओं से निपटने के संकल्प को दोहराया गया. साथ ही, इस बात पर जोर दिया गया कि आतंकवाद को किसी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. ब्रिक्स ने आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस अपनाने, इसमें शामिल लोगों की जवाबदेही तय करने और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने का आह्वान किया. ब्रिक्स ने संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के तहत 'अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन' को जल्द से जल्द फाइनल रूप देने और उसे अपनाने की भी मांग की.

सितारा होटल फुल, 6.2 लाख रुपये तक एक रात का किराया

11 सितंबर से अगले 5 दिनों की बुकिंग फुल

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 12 सितंबर. 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का असर राजधानी के लग्जरी होटलों पर भी दिख रहा है. ब्रिक्स प्रतिनिधियों, साझेदार देशों के प्रतिनिधियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दिल्ली में 3,000 से ज्यादा कमरे बुक किए गए हैं.

मांग बढ़ने के साथ कई पांच सितारा होटलों में कमरों का किराया कई लाख रुपये प्रति रात तक पहुंच गया है. द लीला पैलेस नई दिल्ली में कुछ कमरों का किराया 6.2 लाख रुपये प्रति रात तक दिख रहा है. होटल की वेबसाइट पर 11 सितंबर से आगले 5 दिनों की बुकिंग फुल

बताई जा रही है. आईटीसी मौर्या में कमरों का किराया करीब 2.5 लाख रुपये प्रति रात तक पहुंच गया है. यहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ठहरे हैं. पूरा होटल रूसी प्रतिनिधिमंडल के लिए बुक है. द लोधी में कमरों की दर करीब 1.2 लाख रुपये, जबकि ले मेरिडियन नई दिल्ली में करीब 1 लाख रुपये प्रति रात तक पहुंच गई है.

ले मेरिडियन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्षों के साथ युगांडा, नाइजीरिया और मलेशिया के प्रतिनिधिमंडल भी ठहरे है. द ओबेरॉय भी पूरी बुक है. ओबेरॉय में ब्राजील, कजाकिस्तान, इथियोपिया और इंडोनेशिया के अधिकारियों को ठहराया गया है.

डॉलर की बादशाहत पर चोट

ट्रंप की चिढ़ और ब्रिक्स का महा-गठबंधन

अब बिना डॉलर चलेगी आधी दुनिया और बेबस देखते रहेंगे ट्रंप!

नई दिल्ली, 12 सितंबर. अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, उसे महाशैतान कहने वाले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भारत में हैं. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं. उन्होंने ट्रंप को एक नई टेंशन दे दी है. वो कह रहे हैं कि डॉलर का इलाज हम कर कर रहेंगे. उनकी सलाह है कि ब्रिक्स के सभी सदस्य खुद अपना करेंसी चलाएं.

डॉलर पर निर्भरता खत्म करें. अब बहुत बुरी तरह चिढ़ जाएंगे ट्रंप. ईरानी राष्ट्रपति थोड़े दिन पहले बिश्केक में मोदी से मिले थे. तब मोदी ने वहां ताल ठोककर कहा कि भारत और ईरान ट्रेड बास्केट बढ़ाएंगे. जब ट्रंप ने कहा है कि ईरान से ट्रेड करने वाले पर ही 100% टैरिफ लगाएंगे, ऐसे समय में ईरान से व्यापार बढ़ाने की बात करने का मतलब है ये साफ करना कि भारत किसी दबाव में नहीं है.पुतिन के बेहद खास और क्रेमलिन के प्रवक्ता डिमित्री पेस्कोव ने भी कहा है कि ब्रिक्स देश अब 90% पैसा अपनी लोकल करेंसी में लेते देते हैं.

साफ़ तौर पर इशारा है कि क्या होने जा रहा है. दिल्ली के इस महाजमघट में जहां पूरी दुनिया की आबादी का आधा हिस्सा मौजूद है तो क्या ही किसी की दादागिरी चलेगी.और पेस्कोव ने भी यही कहा कि ट्रंप डॉलर को हथियार की तरह यूज़ कर रहे हैं उससे निपटने की जरूरत है. तियानजिन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तस्वीर देखकर भी ट्रंप चिढ़ गए थे. इस बार तो उनके खास सर्जियो गोर नई दिल्ली में तैनात हैं. उन्हें पल-पल की खबर पहुंचा रहे होंगे. अब सवाल है कि ब्रिक्स क्या कर सकता है. इसे समझने के लिए ब्रिक्स बैंक को समझना जरूरी है. इसकी स्थापना 2014 में हुई थी फोर्टालेजा समिट के दौरान.

तियानजिन में जब मिले थे पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग

तो इसकी जो फंडिंग है और जो लोन डिसबर्समेंट है इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड जारीकर पैसा इकट्ठा किया जाता है. उस फंड से ये बुनियादी ढांचा, स्वच्छ ऊर्जा, ट्रांसपोर्टेशन, शहरी विकास जिस देश को मेंबर को जरूरत है, वह इससे लोन ले सकता है.यहां आईएमएफ की तरह और वर्ल्ड बैंक की तरह किसी को वीटो या किसी एक देश का दबदबा नहीं चलता.

सुरक्षा जिनपिंग के पहुंचने से पहले ही पूरे इलाके, रूट, होटल और संभावित खतरे को न्यूट्रलाइज कर दिया गया

जमीन से आसमान तक अभेद्य घेरे में जिनपिंग

नई दिल्ली, 12 सितंबर. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए शनिवार शाम नई दिल्ली पहुंच चुके हैं. उनकी सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर आसमान तक अभेद्य घेरा बनाया गया है. चीनी सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं.

जिनपिंग की सुरक्षा की सबसे अहम बात है कि खतरा सामने आने का इंतजार नहीं, बल्कि जिनपिंग के पहुंचने से पहले ही पूरे इलाके, रूट, होटल और संभावित खतरे को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है. सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ उनके आसपास तैनात सुरक्षाकर्मियों तक सीमित नहीं है. उनकी सुरक्षा में इलाके को कंट्रोल में लेने से पहले सुरक्षा ऑडिट, टेक्निकल सर्विलांस और विशेष सुरक्षा वाहनों का इस्तेमाल आदि प्रक्रिया पूरी की गई.

विदेशी धरती पर शौच भी छोड़ते

दुनिया के ताकतवर नेताओं की सुरक्षा सिर्फ बुलेटप्रूफ कार, हथियारबंद कमांडो और सुरक्षित रास्तों तक सीमित नहीं रहती. विदेश यात्रा के दौरान उनकी निजी जिंदगी की छोटी से छोटी चीज भी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है. 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था इसी का उदाहरण है. रिपोर्टों के मुताबिक, शी के साथ निजी पोर्टेबल टॉयलेट की व्यवस्था भी जुड़ी है, ताकि उनके जैविक अपशिष्ट को विदेशी जमीन पर छोड़े जाने से रोका जा सके. इसके पीछे संभावित मेडिकल जानकारी के लीक होने और जैविक नमूनों के विश्लेषण से उनकी सेहत से जुड़े राज सामने आने की आशंका बताई जाती है.

एयरस्पेस तक की निगरानी

विदेश यात्रा के दौरान चीनी एजेंसियों ने दिल्ली के एयरस्पेस, वेंटिलेशन सिस्टम और हवा के फ्लो तक की जांच की है, ताकि किसी संभावित खतरे को पहले ही पहचाना जा सके.

सेंट्रल गार्ड ब्यूरो तैनात

जिनपिंग की मुख्य सुरक्षा सेंट्रल गार्ड ब्यूरो ने संभाल रखी है. इसमें पीएलए के बेहद चुनिंदा और वफादार कमांडो शामिल हैं. जिनपिंग जिनके घेरे से बाहर नहीं जाते.

एआई फेसियल रिकग्निशन और साइबर इंटेलिजेंस

सुरक्षा व्यवस्था में एआई आधारित फेसियल रिकग्निशन कैमरे और एडवांस साइबर इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल गया है. संदिग्ध गतिविधियों और लोगों की पहचान यह तकनीक अहम है.

बुलेटप्रूफ लिमोजिन- जिनपिंग के लिए चीन की विशेष होंगछी एन701 लग्जरी कार लिमोजिन का इस्तेमाल किया गया है. इसे बेहद उच्च सुरक्षा वाली आधिकारिक कार के तौर पर तैयार किया गया है और रिपोर्टों में इसे रॉकेट हमले जैसे खतरों से सुरक्षा देने में सक्षम बताया गया है. यह राष्ट्रपति के वाहनों का काफिला उनके भारत आने से पहले ही दिल्ली पहुंच चुका था और इसी लिमोजिन से एयरपोर्ट से रवाना हुए.